
Under CSR Support by
ipca | Foundation
missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER
ARJUN BATCH
Class 9th
Economics
mg
भारत में खाद्य सुरक्षा
अध्याय-4 | भाग-4

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

आज क्या पढेंगे ?

1 सार्वजनिक वितरण प्रणाली

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

PDS प्रणाली

लाभ-

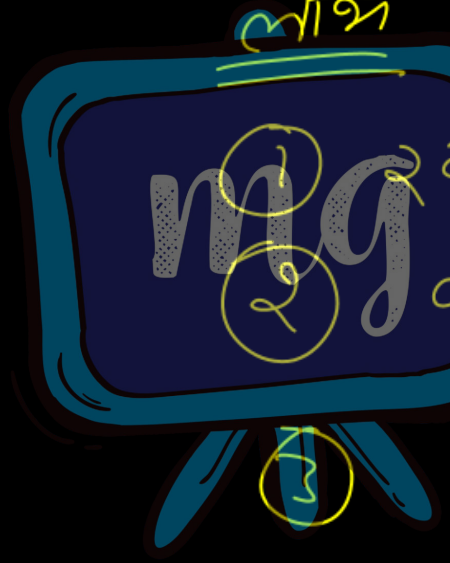

1. खाद्यान्न की कमी को दूर रखने में सहायता मिली है।
2. कीमतों में स्थिरता
3. कम आय वाले व्यक्तियों को सुरक्षा दी जाती है।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

PDS की आलोचना

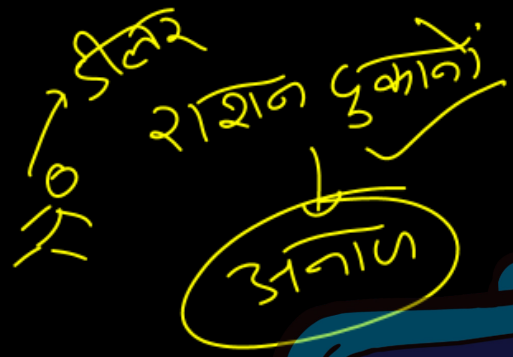



- भंडारण बोझ
- लागत अधिक
- बफ़र स्टॉक की बर्बादी
- डीलरों की समस्याएं :-
  (i) जमाखोरी
- महंगाई को भी बढ़ावा

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER



MSP

पीडीएस की आलोचनाएँ

1. भंडारण बोझ
2. मुद्रा स्फ़ीति / महंगाई
3. केवल गेहूं और चावल
4. जल स्तर में कमी
5. पीडीएस डीलर के साथ समस्याएं

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER



1 भंडारण बोझ

- एमएसपी के कारण सरकार को आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न खरीदना पड़ता है।
- बड़े भंडार बनाए रखना महँगा है।
- कुछ अनाज सड़ रहे हैं और चूहे उन्हें खा रहे हैं।
- अनाज की बर्बादी और गुणवत्ता में गिरावट।
- अनाज के भंडार भरे होने के बावजूद भुखमरी के मामले आम हैं।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

MSP
किन राज्यों
कृषक ज्यादा से ज्यादा उत्पादन

मुद्रा स्फ़ीति / महंगाई

- कुछ राज्य (पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश) उच्च एमएसपी की पैरवी करते हैं।
- इससे मुद्रास्फीति बढ़ती है।

महंगाई



Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

केवल गेहूं और चावल

- एमएसपी से मुख्य रूप से गेहूँ और चावल उत्पादकों को लाभ होता है।
- यह दालों जैसी अन्य फसलों की उपेक्षा करता है।



Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER



जल स्तर में कमी

- किसान मोटे अनाज की बजाय गेहूं और चावल की खेती की ओर रुख कर रहे हैं।

कारण

- इन अनाजों के लिए उच्च एमएसपी
- इन फसलों को अधिक पानी की आवश्यकता थी। ∴ जल स्तर में कमी

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER



पीडीएस डीलर के साथ समस्याएँ

- बेहतर मुनाफ़े के लिए अनाज को खुले बाज़ार में बेचना।
- राशन की दुकानों पर घटिया गुणवत्ता वाला अनाज बेचना।
- दुकानों का अनियमित रूप से खुलना।

जमाखोरी

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER



PDS (1942-45)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गिरावट

बाजार कीमतों पर खाद्यान्न खरीदना

⇒ वर्तमान में PDS में संशोधन

RPDS

TPDS

APL → निर्धनता रेखा

- लक्षित समूह
- उचित कीमतों पर खाद्यान्न
  - BPL
  - APL की उपेक्षा

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

2000
AAY
25 Kg
2002

ANTYODAYA YOJANA (AA

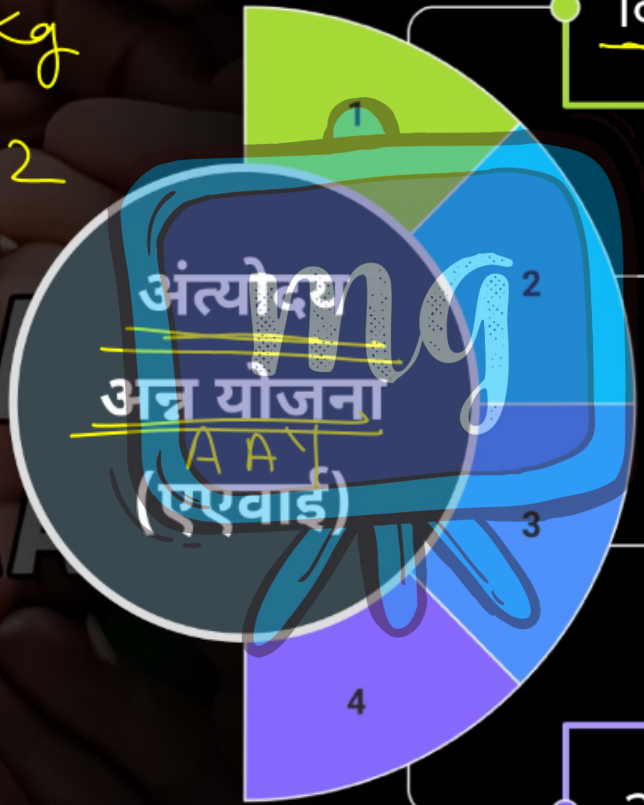

- दिसंबर 2000
- सब्सिडी वाले खाद्यान्न
- राज्य ग्रामीण विकास विभाग
- 35 किग्रा/परिवार

गेहूँ → ₹ 2
चावल → ₹ 3

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

सब्सिडी

- सरकार
- भुगतान
- किसानों, उत्पादकों, उपभोक्ताओं
- आर्थिक सहायता
- लागतों में कमी

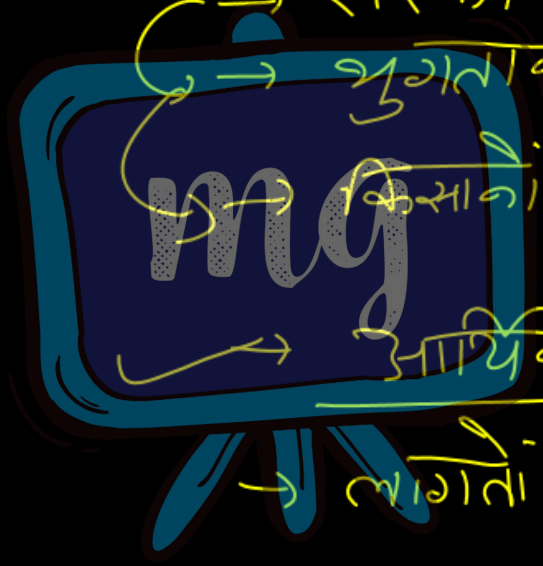

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

खाद्य सुरक्षा में सहकारी समितियों की भूमिका



- सहकारी समितियाँ आवश्यक वस्तुओं को कम कीमतों पर बेचने के लिए दुकानें स्थापित करती हैं।
- तमिलनाडु में, लगभग 94% उचित मूल्य की दुकानें सहकारी समितियों द्वारा संचालित की जाती हैं।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

सहकारी समितियों के

उदाहरण :-

1. मदर डेयरी (दिल्ली)
2. अमूल (गुजरात)



Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

महाराष्ट्र

- विकास विज्ञान अकादमी ने गैर-सरकारी संगठनों को अनाज बैंक स्थापित करने में मदद की है।
- एडीएस गैर-सरकारी संगठनों के लिए खाद्य सुरक्षा पर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है।



Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

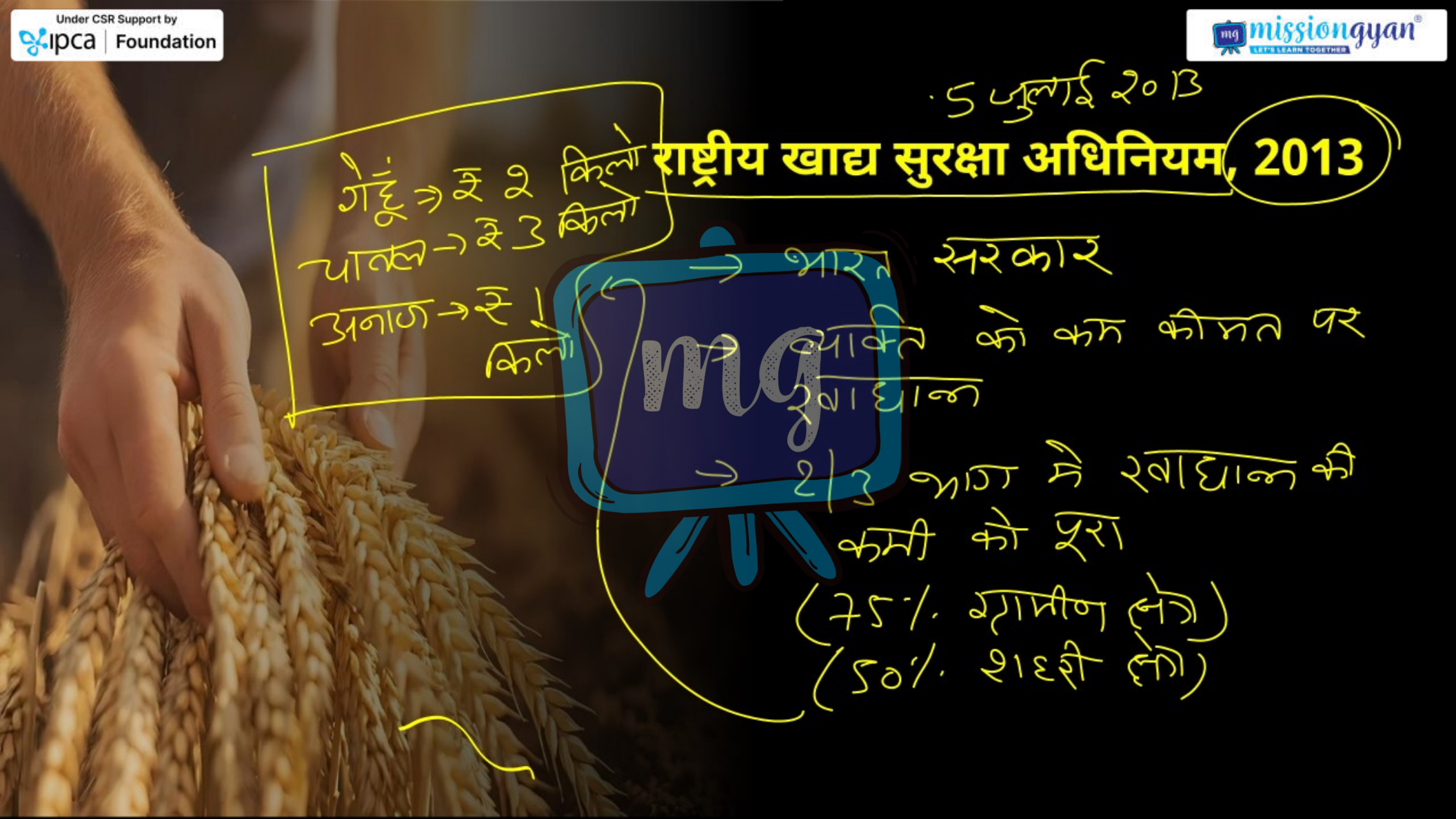

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013

- 5 जुलाई 2013
- भारत सरकार
- व्यक्ति को कम कीमत पर खाद्यान
- 2/3 आबादी को खाद्यान की कमी को पूरा
  - (75% ग्रामीण लोग)
  - (50% शहरी लोग)

गेहूं → ₹ 2 किलो
चावल → ₹ 3 किलो
अनाज → ₹ 1 किलो

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

सब्सिडी

Q) किसके द्वारा दी जाती है?

→ सरकार → भुगतान

Q) किन-किन व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाती है?

→ उत्पादकों, किसानों, उपभोक्ता (उज्जवला योजना)